भारत को सशक्त करता डिजिटल लेनदेन

✍ डॉ. संजय कुमार*

पैसा मनुष्य के लिए हमेशा से ही उपयोगी रहा है और धन-दौलत ही सशक्तीकरण का पैमाना रहा है। धन के इसी महत्व को रेखांकित करते हुए राजा भर्तृहरि ने कहा था - 'सर्वेगुणा: काञ्चनमाश्रयन्ते'। फिर आज का युग तो आर्थिक युग है जहाँ सब कुछ अर्थ से ही संचालित होता है। समय के साथ धन के स्वरूप और लेनदेन के माध्यम में भी बदलाव आया है। शुरु-शुरू में जब मुद्रा का चलन नहीं था तो लोग गायों को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करते थे। क्रमश: अनाज, स्वर्ण, रजत, कौड़ी, धेला आदि विनिमय का माध्यम बने। कालांतर में धातु मुद्रा का आविष्कार हुआ और सोने, चाँदी, तांबे, कांसे आदि से निर्मित सिक्कों के माध्यम से लेनदेन संपन्न होने लगा। फिर काग़ज़ी मुद्रा का दौर आया जिसने लेनदेन को और भी अधिक सुविधाजनक बना दिया। उन्नीस सौ अस्सी-नब्बे के दशक में जब सूचना प्रौद्योगिकी ने दस्तक दी तो इसने अन्य के साथ-साथ बैंकिंग लेनदेन के तौर-तरीकों को भी बदलकर रख दिया। सूचना प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग को न केवल भारी-भरकम लेखा-बहियों और शाखाओं की चारदीवारी से बाहर निकाला, अपितु उसे डिजिटल बैंकिंग के रूप में सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक बनाया। इसने जहाँ एक ओर भौतिक मुद्रा की आवश्यकता को समाप्त किया, वहीं भुगतान पद्धति को द्रुतगामी बनाकर आर्थिक क्रियाओं के संचालन को भी तेज किया है। इसके कारण अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। इंटरनेट की बढ़ती पैठ, स्मार्टफोन की सुलभता, सस्ता डेटा और टेक-सेवी होती नई पीढ़ी आदि ऐसे कारक हैं जिनके कारण डिजिटल लेनदेन बहुत ही तीव्र गति से भौतिक लेनदेन को प्रतिस्थापित कर रहा है। यह न केवल व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है, अपितु देश के सशक्तीकरण की आधारशिला भी तैयार कर रहा है। डिजिटल लेनदेन किस तरह से देश को सशक्त कर रहा है, पर विस्तार से प्रकाश डालने के पूर्व डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन के विविध आयामों पर विहंगम दृष्टि डाल लेना प्रासंगिक होगा।

डिजिटल बैंकिंग क्या है?

डिजिटल का शाब्दिक अर्थ है, अंकों से सूचना देना। प्रौद्योगिकी के संदर्भ में डिजिटल उस इलेक्ट्रॉनिक पद्धति को कहते हैं जो दो अवस्थाओं (पॉज़िटिव अर्थात् 1 और नॉन-पॉज़िटिव अर्थात् 0) में डेटा उत्पन्न, संग्रहीत और संसाधित करती है। वहीं डिजिटल बैंकिंग का आशय पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं का स्वचालन है। डिजिटल बैंकिंग बैंक के ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। यह भौतिक रूप से होने वाले सभी बैंकिंग परिचालनों जैसे - धन अंतरण, बचत खाता प्रबंधन, ऋण प्रबंधन, यूटीलिटी बिलों का भुगतान, चेक प्रबंधन, बैंक स्टेटमेंट, बीमा, निवेश, बैलेंस पूछताछ आदि को डिजिटाइज़ करने की प्रक्रिया है ताकि बैंकिंग सेवाओं के उपभोक्ताओं को इनके लिए बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता न पड़े। यह सभी काग़ज़ी कार्रवाइयों जैसे चेक, पे-इन स्लिप, डिमांड ड्राफ्ट आदि से मुक्ति के साथ-साथ चौबीसों घण्टे बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी उपक्रम है। भारत में प्रचलित कुछ प्रमुख डिजिटल भुगतान पद्धतियाँ हैं: बैंकिंग कार्ड, यूएसएसडी,

*सहायक महाप्रबंधक(राजभाषा), भारतीय रिज़र्व बैंक।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, भारत इंटरफेस फॉर मनी, बैंक प्रीपेड कार्ड, प्वाइंट ऑफ सेल, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग़ आदि। जब हम डिजिटल लेनदेन की बात करते हैं तो इसका आशय उस लेनदेन से है जहाँ वस्तुओं/सेवाओं आदि के लिए भुगतान नकदी की बजाए इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किया जाता है।

डिजिटल लेनदेन और राष्ट्र का सशक्तीकरण

डिजिटल लेनदेन जहाँ नागरिकों के लिए सुविधाजनक और उपयोगी सिद्ध हो रहा है, वहीं यह राष्ट्र के सशक्तीकरण का हेतु भी बन रहा है। इस पहलू को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे :

हर समय लेनदेन: शाखा बैंकिंग में जहाँ लेनदेन का समय निश्चित होता है, वहीं डिजिटल लेनदेन कहीं से, कभी भी किया जा सकता है। इसके कारण ग्राहकों के उस समय की बचत हुई जो बैंक शाखा जाकर लेनदेन करने में खप जाता था। यही स्थिति कारोबारी लेनदेन के मामले में भी है। जब भौतिक रूप से भुगतान होता था तो व्यक्ति किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान/दुकानदार आदि को दुकान/प्रतिष्ठान खुलने पर ही भुगतान कर पाता था, किंतु जब से डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था शुरू हुई वह अपनी सुविधानुसार किसी भी समय भुगतान कर पा रहा है। पहले यदि किसी दूरस्थ आपूर्तिकर्ता से माल मंगाना होता था तो उसे एड़वांस में पैसा भेजना पड़ता था। पैसा चेक, ड्राफ्ट या किसी व्यक्ति के जरिए भेजा जाता था जिसके कारण पैसा पहुँचने और माल प्राप्त होने में पंद्रह-बीस दिन लग जाते थे। इस विलंब के कारण कभी-कभी फुटकर कारोबारी बाजार की अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाने से वंचित रह जाते थे। पर जब से डिजिटल लेनदेन शुरू हुआ, वह नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई जैसे किसी भी माध्यम से पलक झपकते पैसा भेज सकता है और माल डिलीवरी की प्रक्रिया को तुरंत प्रारम्भ करा सकता है। डिजिटल लेनदेन से जहाँ लोगों का समय, श्रम और आने-जाने का खर्च बच रहा है, वहीं समय की इस बचत का उपयोग वे अपने कारोबार या अन्य उत्पादक गतिविधियों में कर पा रहे हैं। जब व्यक्ति चौबीसों घण्टे लेनदेन कर सकता हो, तो जाहिर है कि वह चौबीसों घण्टे कारोबार भी कर सकता है। कारोबार अवधि में विस्तार होना, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार है और इसका सीधा फायदा अर्थव्यवस्था को पहुंचता है।

लेनदेन की लागत में कमी: डिजिटल लेनदेन मुद्रा के भौतिक लेनदेन और अन्य कागज़ी लेनदेनों (जैसे चेक, ड्राफ्ट आदि) के मुकाबले काफी सस्ता है। जब डिजिटल लेनदेन नहीं था, तो भुगतान के लिए व्यक्ति को ईंधन अथवा किराया खर्च करके बैंक जाना पड़ता था और यदि बैंक-ड्राफ्ट आदि बनवाना हो तो उसके लिए कमीशन अलग से अदा करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त सरकार को जहां नोट/सिक्का आदि के मुद्रण/ढ़लाई का खर्च वहन करना पड़ता था, वहीं बैंकों को लेनदेन हेतु चेक, ड्राफ्ट और अन्य दस्तावेज़ों का मुद्रण कराना पड़ता था। सबसे बड़ा खर्च मुद्रा के परिवहन, रखरखाव और उस हेतु नियोजित कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर होता था। डिजिटल लेनदेन ने इन सभी प्रकार के खर्चों पर लगाम लगाई है और इसके कारण धन की जो बचत हुई है, उसका उपयोग अन्य विकासात्मक गतिविधियों पर कर पाना संभव हुआ है।

आधारभूत ढाँचे की बचत/संसाधनों की बचत: डिजिटल बैंकिंग के कारण बैंक शाखाओं में ग्राहकों का आवागमन घटा है जिससे न तो शाखा के लिए अधिक स्पेस की आवश्यकता रही और न ही अतिरिक्त काउंटर खोलने हेतु आवश्यक फर्नीचर, विद्युत उपकरण आदि लगाने की। संसाधनों की यही बचत गैर-बैंकिंग प्रतिष्ठानों में भी हुई है। उदाहरण के लिए पहले बिजली, पानी, टेलीफोन, गैस आदि के बिलों, टिकिट बुकिंग, स्कूल फीस, विभिन्न प्रकार के कर आदि जमा करने के लिए तमाम काउंटर खोलने पड़ते थे, किंतु जब से डिजिटल लेनदेन शुरू हुआ इनकी आवश्यकता ही न रही। डिजिटल लेनदेन के कारण संसाधनों की बचत केवल सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, अपितु निजी क्षेत्र भी इससे खूब लाभांवित हुआ है। मिसाल के तौर पर आज ऑनलाइन ऑर्डर पर माल की आपूर्ति होना आम बात हो गई है जिससे निजी प्रतिष्ठानों में भी ग्राहकों की आवाजाही घटी है। इसके कारण उन्हें भी

चमचमाते एयरकंड़ीशंड शोरूम, दुकान आदि के लिए बड़े स्पेस की आवश्यकता नहीं रही। वे किसी दूरस्थ जगह पर स्थित गोदाम आदि से ऑनलाइन आर्डरों पर सप्लाई करने लगे। इसके कारण भूमि, बिजली, पानी जैसे संसाधनों की बचत हुई है। दुर्लभ संसाधनों की बचत करना भी राष्ट्र निर्माण का काम है।

लेनदेन में पारदर्शिता: नकद लेनदेन में जहाँ लेनदेन की हर समय रसीद या साक्ष्य मिल पाना मुश्किल है, वहीं डिजिटल लेनदेन अपने आप में एक रसीद है। चूँकि भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है, अतएव, लेनदेन की पूरी श्रंखला को ट्रैक किया जा सकता है। इसके कारण भुगतान प्राप्ति से जुड़े तमाम तरह के विवादों से मुक्ति मिली है और क्रेता-विक्रेता, सेवा प्रदाता- उपभोक्ता के संबंध बेहतर हुए हैं और परस्पर भरोसा बढ़ा है। दूसरी बात लेनदेन के लेखांकन को लेकर है। भुगतानकर्ता और भुगतान प्राप्तकर्ता दोनों को प्रत्येक लेनदेन के लेखांकन के लिए किसी भी प्रकार के काग़ज़, कलम, डायरी या इस हेतु किसी मुनीम आदि को रखने की आवश्यकता नहीं है। हर लेनदेन स्वत: ऐप और खाते में परिलक्षित हो जाता है और उसकी रीयलटाइम में अकाउंटिंग होती रहती है।

त्वरित भुगतान: कहते हैं कि पैसा जितना तेजी से घूमता है, आर्थिक क्रियाएं भी उतनी तेजी से चलती हैं। पहले जब पैसा भौतिक रूप से या चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से भेजा जाता था तो उसे गंतव्य तक पहुँचने में काफी समय लग जाता था। इस अवधि के दौरान वह निष्क्रिय पड़ा रहता था। गंतव्य तक पहुँचने के बाद ही वह उत्पादक गतिविधियों में नियोजित हो पाता था। किंतु डिजिटल लेनदेन के कारण पैसा एक छोर से दूसरे छोर पर तत्काल पहुँच जाता है जिससे आर्थिक चक्र सतत् प्रवर्तनशील रहता है। किसी भी देश के स्थायी विकास के लिए वहाँ आर्थिक गतिविधियों का निरंतर चलायमान रहना अत्यंत आवश्यक है।

सुरक्षित और सुविधाजनक भुगतान: नकद भुगतान के मामले में भुगतान प्राप्तकर्ता को कई बार काफी दूरी तय करनी पड़ती है जिसमें पैसे की चोरी, लूटपाट अथवा जान जोखिम में पड़ने की संभावना भी रहती है। वहीं डिजिटल भुगतान काफी सुरक्षित है क्योंकि लेनदेन करने के लिए इसमें कई स्तरों पर प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा नकदी लेकर चलना अपने आप में असुविधाजनक है, खासकर तब जब छोटे मूल्यवर्ग के नोट अथवा बड़ी मात्रा में सिक्के हों। वहीं डिजिटल लेनदेन के मामले में आपका स्मार्टफोन ही पर्याप्त है जिसे आप वैसे भी साथ लेकर चलते हैं। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि नकदी आधारित लेनदेन में जहाँ रुपए गिनने में समय लगता है, वहीं जाली नोटों की आशंका भी बनी रहती है। जबकि डिजिटल लेनदेन फटाफट हो जाता है, इसमें न तो रुपए गिनने का झंझट, न हिसाब लगाने का और न ही जाली नोटों की कोई संभावना है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब से डिजिटल लेनदेन प्रारंभ हुआ है तब से चिल्लर न होने का बहाना बनाकर दो-चार-दस रुपए की चपत लगाने वालों के मंसूबों पर भी पानी फिरा है। उदाहरण के लिए जब नकदी आधारित लेनदेन होता था तब यदि कोई बिल 491 रुपए का आता था तो 500 रुपए का नोट देने पर वह छुट्टे न होने का बहाना बनाकर 9 रुपए की चपत लगा देता था। पर डिजिटल लेनदेन के मामले में तो दशमलव अंकों में भी भुगतान किया जा सकता है। डिजिटल लेनदेन ने कारोबारियों को जेब कतरने या पैसों की चोरी हो जाने के भय से मुक्त किया है जिसके कारण वे देर रात तक आवागमन करने में सक्षम हुए हैं। इससे उनके कारोबार का दायरा और समय बढ़ा है जिसका सकारात्मक प्रभाव प्रत्यक्षत: उनकी आमदनी और परोक्षत: देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है।

ई-कामर्स की जीवनरेखा: आज ई-कामर्स का चलन जोरों पर है और यह डिजिटल बैंकिंग के कारण ही संभव हुआ है। वास्तव में लोगों को सशक्तीकरण का सबसे अधिक आभास ई-कामर्स के कारण ही हुआ है। आज डिजिटल लेनदेन की बदौलत कोई व्यक्ति घर बैठे रोजमर्रा के उपयोग की सभी चीजें मंगा सकता है। किसी को उपहार उसके पते पर डिलीवर करा सकता है। अब से बीस-तीस बरस पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि

घर बैठे भोजन, पेय अथवा साग-भाजी मंगाई जा सकती है। लेकिन ई-कामर्स ने इसे संभव कर दिखाया है जो डिजिटल लेनदेन की कड़ी की बदौलत ही संभव हुआ है। अब तो दूर देश में बैठा व्यक्ति अपने घर पर स्थित बच्चों या परिवार के सदस्यों को खाद्य पदार्थों की ऑनलाइन डिलीवरी करा सकता है। वह कहीं से, कभी भी किसी के लिए टिकिट बुक कर सकता है, उसके यूटीलिटी बिलों का भुगतान कर सकता है। इसके कारण लोगों के भ्रमण का दायरा विस्तृत हुआ है, उनमें आत्मविश्वास जगा है और दूसरों पर निर्भरता घटी है। आज उसका स्मार्टफोन बैंक भी है और कैश भी है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल लेनदेन के चलते लोगों का सड़कों पर आवागमन कम हुआ है जिसके कारण भीड़, जाम, पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण-जन्य बीमारियों व तदजन्य मानसिक तनाव में कमी आई है। समग्र रूप से देखा जाए तो डिजिटल लेनदेन ने लोगों को हर प्रकार से सशक्त किया है।

कर राजस्व का ज़रिया: किसी भी राष्ट्र के सशक्तीकरण के लिए उसका वित्तीय मोर्चे पर अव्वल रहना बहुत ज़रूरी है। वित्तीय सुदृढ़ता के लिए सरकार के आमदनी के स्रोत अच्छे होने चाहिए। इन स्रोतों में कर-राजस्व आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। जब लोग डिजिटल लेनदेन करेंगे तो रुपया कहाँ से आया और कहाँ गया इसका पता चलेगा। इससे बहुत सारे लोग कर के दायरे में आएंगे और तमाम प्रकार की कर-चोरी रूकेगी। इससे कालेधन पर अंकुश लगेगा। किसी भी देश के सशक्तीकरण के लिए उसकी अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता का होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वित्तीय और मौद्रिक नीतियाँ औपचारिक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। यदि अर्थव्यवस्था में कालाधन अधिक होगा तो कीमतें स्थिर रखने की सरकार और केंद्रीय बैंक की नीतियाँ प्रभावकारी नहीं होंगी। कीमतों में अस्थिरता की सबसे अधिक चोट गरीब तबगे पर पड़ेगी। कर-राजस्व बढ़ने से सरकार के पास गरीबों/वंचितों को समावेशी प्रगति का सहयात्री बनाने हेतु पर्याप्त आर्थिक संसाधन होंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1944 में अपने फिडेल्फिया घोषणा पत्र में कहा था कि दुनिया में यदि किसी भी कोने में गरीबी है तो वह अमीरी के लिए सर्वत्र खतरा है।[1] भारत जैसे दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में जहाँ लगभग 25% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं[2], में राष्ट्र के सशक्तीकरण के पूर्व जन-जन का सशक्तीकरण बहुत आवश्यक है और इस काम में डिजिटल लेनदेन की महती भूमिका है।

भ्रष्टाचार पर अंकुश: डिजिटल लेनदेन के कारण उन सभी प्रकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है जिनकी नकद लेनदेन के मामले में काफी संभावना रहती थी। लाभार्थियों और लक्षित उद्देश्यों के लिए धन बगैर किसी रिसाव के गंतव्य तक पहुंच रहा है। इससे जनता का जहाँ एक ओर प्रणाली में भरोसा बढ़ रहा है, वहीं ठोस विकास की अवधारणा भी मूर्त रूप ले रही है।

अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देना: अध्ययनों से पता चला है कि नकद मुद्रा खर्च करने में लोगों को जो झिझक रहती है, वह डिजिटल लेनदेन में नहीं होती है क्योंकि उसे पैसा हाथ से जाते हुए नहीं दिखता है। इसके अलावा नकदी के प्रति जो मोह या संचय की भावना रहती है, वह डिजिटल लेनदेन में नहीं होती है, लिहाज़ा लोग धड़ल्ले से खर्च करते हैं। लोगों के खर्च करने से अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिलता है। मांग उत्पादन को प्रेरित करती है और इससे रोजगार व आय का सृजन होता है जो पुन: मांग को बढ़ावा देता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की मज़बूती के लिए वहाँ मांग का बने रहना बहुत आवश्यक है। आज डिजिटल ऋण की परंपरा भी चल पड़ी है। खासकर जब आप ई-कामर्स प्लेटफार्म से घरेलू उपयोग की कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं तो 'बाय नाउ पे लैटर' जैसे ऑफर भी दिए जाते हैं। इससे व्यक्ति पैसा न होते हुए भी खरीदारी करने में सक्षम हो जाता है। डिजिटल ऋण की सुलभता जहाँ प्रत्यक्ष तौर पर क्रय क्षमता को बढ़ा देती है, वहीं परोक्षत: यह मांग को सहारा देती है।

सुशासन और शांति कायम रखना: नकद आधारित लेनदेन जहाँ कालेधन में इज़ाफा करता है, वहीं यह अवैध गतिविधियों को पोषित करने का जरिया भी बनता है।

[1]The ILO Declaration of Philadelphia,1944
[2]https://niti.gov.in/sites/default/files/2020-05/press-note-poverty-2011-12-23-08-16.pdf

आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने, तस्करी, ड्रग्स तथा अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए लेनदेन अकसर नकद रूप में किया जाता है जिसके कारण लेनदेन की पूरी श्रंखला को ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों की फंडिंग में भी प्राय: नकदी का इस्तेमाल होता है। जब सभी लेनदेन डिजिटल होंगे और अर्थव्यवस्था नकदी रहित होगी तो एक ओर जहाँ अवैध गतिविधियों की फंडिंग रुकेगी, वहीं लेनदेन के सूत्रों को जोड़ते हुए अपराधियों तक भी पहुँचा जा सकेगा। किसी भी देश की सतत् प्रगति के लिए वहाँ शांति और सुशासन का होना बहुत ज़रूरी है और डिजिटल लेनदेन इस उद्देश्य को पूरा करने में बखूबी कारगर है।

विदेशों में लोकप्रिय होती भारतीय डिजिटल लेनदेन पद्धति: यदि भारत के डिजिटल लेनदेन के आंकडों पर गौर करें तो पाते हैं कि वर्ष 2022 में नकदी रहित लेनदेन में यूपीआई लेनदेन का हिस्सा 77% था। आज यूपीआई की लोकप्रियता केवल भारत के भीतर ही नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी इसकी कामयाबी का डंका बज रहा हैं। इसकी खूबियों से प्रभावित होकर विश्व के कई देश अपने यहाँ लेनदेन में इस माध्यम को जगह दे रहे हैं। इस कड़ी में संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सिंगापुर एवं फ्रांस का नाम उल्लेखनीय है। विदेशी धरती पर यूपीआई की स्वीकार्यता के कारण डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं पर हमारी निर्भरता घटेगी और रुपए में भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। इससे विदेशी मुद्रा की मांग घटेगी। विदेशी मुद्रा की बचत हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति को अनुकूल बनाएगी जिसके कारण देश की साख में बढ़ोतरी होगी। जब किसी देश की साख सुधरती है तो वह विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है और इससे विकास को एक नई गति मिलती है।

डिजिटल लेनदेन- कतिपय चुनौतियाँ

हालांकि डिजिटल लेनदेन को लोग काफी तेजी से आत्मसात कर रहे हैं पर इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती अशिक्षा है। भारत में लगभग 25% जनसंख्या अशिक्षित है।[3] उसके लिए भौतिक बैंकिंग कर पाना ही मुश्किल है, डिजिटल बैंकिंग तो दूर की कौड़ी है। दूसरी बड़ी समस्या गरीबी है, जिसके कारण हर कोई स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर जैसे डिजिटल गैजेट्स खरीद नहीं सकता। चूँकि डिजिटल लेनदेन के लिए डिजिटल डिवाइस होना आवश्यक है, अतएव इनके अभाव में बहुत से लोग डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था को अपना नहीं पा रहे हैं।

साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव तथा साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाएं भी डिजिटल लेनदेन को हतोत्साहित कर रही हैं। भारत की विशाल जनसंख्या के अनुपात में साइबर सेल काफी कम हैं, और जो हैं भी वहाँ साइबर विशेषज्ञों की कमी है। बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों तथा पुलिस के बीच बेहतर समन्वय का अभाव भी साइबर धोखाधड़ी को फलने-फूलने का अवसर प्रदान कर रहा है।

लोगों की कर-चोरी की प्रवृत्ति भी डिजिटल लेनदेन की राह में एक बड़ा रोड़ा है। आज भी बहुत से कारोबारी अपने वास्तविक टर्न-ओवर को छिपाने के लिए नकदी आधारित लेनदेन को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे कारोबारियों के साथ लेनदेन करने वाले लोग मजबूरन नकदी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

यद्यपि डिजिटल लेनदेन के मार्ग में उपर्युक्त अवरोध अवश्य हैं, पर आज के प्रौद्योगिकी-प्रधान दौर में डिजिटल लेनदेन के बगैर काम चलने वाला नहीं है। आज की टेक-सेवी पीढ़ी जब हर काम को डिजिटली करना पसंद कर रही है तो फिर लेनदेन के लिए वह मैन्युअल तरीका क्यों अपनाए। फ्रांसीसी कवि और उपन्यासकार विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि पृथ्वी पर कोई शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आचुका है। उनकी यह बात डिजिटल लेनदेन के मामले में भी प्रासंगिक है। आज यदि एक मामूली-सा रेहड़ी पटरी वाला क्यूआर कोड रखे हुए है, तो वह इसलिए क्योंकि उसे मालूम है कि इसके अभाव में वह बिजनेस खो देगा।

[3]https://www.census2011.co.in/

निष्कर्ष

अंत में सारांश के तौर पर कहा जा सकता है कि डिजिटल लेनदेन आज मनुष्य के लिए वरदान से कम नहीं है। इसने न केवल लोगों की जिंदगी को आसान किया है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। जब लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव उनकी कार्यक्षमता और संस्थानों की उत्पादकता पर पड़ता है। इसने संस्थानों में मानव संसाधन के साथ-साथ अन्य संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया है और सरकार के कर-राजस्व में इज़ाफा किया है। जब देश के नागरिक और संस्थाएं सशक्त होती हैं, तो देश स्वतः सशक्त होने लगता है। भारत में डिजिटल लेनदेन का भावी परिदृश्य बहुत ही उत्साहजनक है। यहाँ जैसे-जैसे आम लोगों के बीच स्मार्टफोन का चलन बढ़ता जाएगा, वे डिजिटली सक्रिय होते जाएंगे और रोजमर्रा से जुड़े तमाम क्रियाकलापों में डिजिटल लेनदेन को अपनाते जाएंगे। यह कहना ग़लत न होगा कि नई सोच का यह नया भारत अब उपलब्धियों के नए-नए प्रतिमान गढ़ रहा है। यदि वर्ष 2023 की दो महान उपलब्धियों की बात की जाए जिसने विश्व समुदाय का भारत की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, तो उनमें से एक है चंद्रयान-3 की सफलता और दूसरा है, यूपीआई लेनदेन की व्यापक स्वीकार्यता। भारत में बहुत ही अल्प समय में डिजिटल लेनदेन ने सफलता की जो ऊँचाइयाँ हासिल की हैं, वह न केवल देश के लिए गर्व का विषय है अपितु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी अनुकरणीय है।

☯

13th R. K. Talwar Memorial Lecture

The Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) organizes the R. K. Talwar Memorial Lecture every year, in association with the State Bank of India (SBI) since 2007. The lecture is organised in memory of Shri. R. K. Talwar, who was the Chairman of SBI from 1969 to 1976. This year, the 13th R. K. Talwar Memorial Lecture will be held on 16th February 2024 at SBI Auditorium, Nariman Point, Mumbai. The lecture will be delivered by Dr. V. Anantha Nageswaran, Chief Economic Adviser, Government of India.